मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता ।

दुनियाँ के मजदूरो, एक हो !

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 22 | अप्रेल 1990 | 50 पैसे

दो नजरिये

अपने दुख-दर्द भरे जीवन को बदलने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर हम एक-दूसरे के विरोधी दो नजरियों को रोजमर्रा की घटनाओं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं । पिछले अंक में हमने देश के प्रश्न को लिया था । वहाँ हमने देखा था कि प्रचलित सोच जहाँ देश को पूजनीय बताती है वहाँ क्रान्तिकारी नजरिया फरीदाबाद धनबाद-कोरिया-इंगलैंड-अमेरिका-रूस के मजदूरों के साझे हितों को उजागर करता है तथा पूंजीवाद के देश-रूपी किलों को तोड़ कर दुनियां के मजदूरों की एकता की राह पर बढ़ने की वकालत करता है । इस अंक में हम हर देश के एक प्रमुख स्तम्भ, फौज पर इन दो नजरियों को देखेंगे ।

फौज के बिना देश की कल्पना तक करना असम्भव है—तोप तलवार चन्द लोगों के एकाधिकार के बिना शोषण वाली व्यवस्था के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता । इसलिये शोषण पर टिकी पूंजीवादी व्यवस्था के सब पक्ष धर भी अपने-अपने देश की फौज को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने के मामले में एकमत हैं । इसीलिये आज हावी नजरिया, जो कि पूंजीवाद नजरिया है, हर देश में फौज के प्रश्न को विवाद से परे एक सवाल के तौर पर पेश करता है । "जय जनरल जवान !" इस प्रचलित सोच का निचोड़ है । किसान-दस्तकार और टटपूंजिये तथा पूंजीवादी विचारों से प्रभावित मजदूर भी इस पूंजीवादी नारे को जोश-खरोश से लगाते हैं ।

दूसरे नजरिये, मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी दृष्टिकोण के मुताबिक सेना लुटेरों का प्रमुख हथियार होती है । पूंजीवादी शोषण के इस दौर में हर देश की फौज वहां कार्यरत पूंजीवाद के नुमाइन्दों का मजदूरों के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है । इतना ही नहीं, इस नजरिये के अनुसार फौज का बनाना ही मजदूर विरोधी कदम है । **क्रान्तिकारी दृष्टिकोण के एक प्रमुख प्रवक्ता, कार्लमार्क्स के मुताबिक पुलिस व फौज भंग करना और आम मजदूरों का हथियार बन्द होना दमन-शोषण वाली पूंजीवादी व्यवस्था को मिटाने के लिये पहली शर्त है हथियारों से लैस मजदूर ही पुलिस फौज को खत्म करके हंसी-खुशी भरे खुशहाल समाज के निर्माण की राह सम्पूर्ण मानव जाति के लिए खोल सकते हैं ।**

1871 में पेरिस में मजदूरों ने हथियार उठाये और पुलिस-फौज को वहाँ भंग करके मजदूर आन्दोलन के लिये मिसाल कायम की । और जगह-जगह पर उभरी क्रान्तिकारी मजदूर पार्टियों ने पुलिस-फौज भंग करने तथा आम मजदूरों को हथियार बन्द करने को अपने कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया । पेरिस के मजदूरों की राह पर आगे बढ़ कर रूस में मजदूरों ने हथियार उठाये और अक्तूबर 1917 में मजदूरों का राज कायम किया । तब पूंजी के नुमाइन्दों ने मजदूरों पर फौजी हमले तेज कर दिये । इस पर मजदूरों की क्रान्तिकारी पार्टी, बोल्शेविक पार्टी ने पूंजीवादियों के फौजी हमलों का मुकाबला करने के लिये खुद भी फौज बनानी शुरू कर दी । भुला दी गई मार्क्स की बातें, आंखें मूंद ली गई पेरिस में मजदूरों के अनुभवों से और लाल फौज के नाम से 1918 में ही रूस में एक नई फौज खड़ी कर दी गई । जल्दी ही रूस में आम मजदूरों से हथियार रखवा लिये गये और लाल फौज का अस्त्र-शस्त्र पर एकाधिकार कायम कर दिया गया । इस प्रकार लाल फौज के नाम वाली फौज से लैस पूंजी के नए नुमाइन्दे रूस में उभरे और मजदूरों को हांकने लगे । उसके बाद के सत्तर सालों में कई और जगह भी लाल फौज, जन मुक्ति सेना, देश भक्त फौज, राष्ट्रीय सेना आदि-आदि के नाम वाली फौजों के जरिये पूंजी के नुमाइन्दे मजदूरों के शोषण को श्रम तथा बन्दूक के बल पर कायम रखने में सफल हुये हैं ।

इस घटनाक्रम से पूंजीवादी नजरिया यह पाठ पढ़ाने की कोशिश करता है कि देश और उसकी रक्षा के लिये पुलिस फौज तो चाहिये ही चाहिये । इसके विपरीत क्रान्तिकारी नजरिया लाल-काले-पीले तिरंगे लेबल वाली सब फौजों के मजदूर विरोधी चरित्र का पर्दाफाश करता है । यह दृष्टिकोण मार्क्स के इन शब्दों को मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है कि **जब तक मजदूरों के हाथों में हथियार हैं तभी तक मजदूर अपने हितों को मजबूती से आगे रख सकते हैं ।**

चीन रूस रोमानिया आदि की हाल की घटनाओं ने लाल फौज नाम वाली फौजों का भांडा फोड़ दिया है पर देश की फौज का भ्रम अभी भी आम मजदूरों में बना हुआ है । दमन-शोषण मिटाने के लिये, पूंजीवाद को दफनाने के लिये और हंसी-खुशी भरे खुशहाल समाज के निर्माण के लिये हर रूप-रंग की फौज को भंग करना तथा आम मजदूरों का हथियारबन्द होना जरूरी है ।

—अ—जी

पूंजीवादी कायदे कानून और मजदूर
बंगाल से एक उदाहरण

हिन्दुस्तान लीवर भारत की बड़ी कम्पनियों में है । खान-पान की वस्तुयें और सौन्दर्य सामग्री बनाने वाली यह कम्पनी इंगलैंड की यूनी लीवर कम्पनी की औलाद है । हिन्दुस्तान लीवर के कई प्रान्तों में कारखाने हैं और लिप्टन, ब्रुकबान्ड तथा क्रीम पावडर बनाने वाली पाइस इसकी सहायक कम्पनियां हैं । दुनियाँ भर के पूंजीवादी अनुभवों से लैस हिन्दुस्तान लीवर मैनेजमेन्ट बहुत शातिर है । इसलिये इस मैनेजमेन्ट के खिलाप मजदूरों के संघर्षों के अनुभव अन्य मजदूरों के भी बहुत काम के हैं । मार्च 89 के अंक में हमने हिन्दुस्तान लीवर मैनेजमेन्ट द्वारा कम्पनी की बम्बई स्थित फैक्ट्री में लम्बी तालाबन्दी करके मजदूरों को दबाने के कदम की कुछ चर्चा की थी । यहाँ हम हिन्दुस्तान लीवर की कलकत्ता स्थित फैक्ट्री में चल रही खींचा-तान की चर्चा करेंगे । सामग्री हमने कलकत्ता से छपने वाली बंगला पत्रिका अरनि और बंगला-हिन्दी पत्रिका श्रमिक इस्तेहार से ली है ।

अन्य फैक्ट्रियों की ही तरह कलकत्ता की हिन्दुस्तान लीवर फैक्ट्री में भी मैनेजमेन्ट के दल्लों की यूनियन थी । अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों की ही तरह इस फैक्ट्री के मजदूरों ने भी यूनियन को मैनेजमेन्ट के एक औजार से मजदूरों के हथियार में बदलने की कोशिश की । जुलाई 1987 के यूनियन चुनावों में कलकत्ता हिन्दुस्तान लीवर फैक्टरी के मजदूरों ने दल्लों की जगह लड़ाकू मजदूरों को जिता दिया । और तब आज की वास्तविकता को छिपाये नकाब की कुछ परतें उघड़नी शुरू हुई ।

हिन्दुस्तान लीवर मैनेजमेंट ने अन्य मैनेजमेंटों की ही तरह मजदूरों द्वारा चुने नये लोगों को अपने माफिक बनाने के लिये कदम उठाये । इसके लिये मैनेजमेंट ने पहला काम तो यह किया कि नये चुने लोगों को मान्यता नहीं दी । इस पर नये चुने लोगों ने कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने शुरू किये । तब मैनेजमेंट ने नये चुने लोगों और उनके खास समर्थकों को फैक्टरी में तंग करना शुरू किया । इस पर भी अपने मन माफिक रिजल्ट न आते देख कर मैनेजमेंट ने चुनाव में हारे दल्लों की संयुक्त कमेटी बना कर अगस्त 1988 में उसे यूनियन के तौर पर मान्यता दे दी । इस संयुक्त कमेटी में कांगरेस और सी पी एम के लोग हैं ।

(शेष अगले पेज पर)

हमारे लक्ष्य हैं:— 1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुंचाने के प्रयास करना । 2. पूंजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बटाना । 3. भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना । 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना ।

समझ, संगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है । बातचीत के लिये बेझिझक मिलें । टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे ।

संपर्क—मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद —121001

एस्कोर्ट्स

माजरा क्या है ?

23 मार्च से एस्कोर्ट्स के फरीदाबाद में 14 और मूरजपुर में यामाहा प्लान्ट में प्रोडक्शन बन्द है। दो हजार के करीब कैजुअल वर्करों को 23 मार्च को ही नौकरी से निकाल दिया गया। बारह हजार परमानेन्ट मजदूरों को मार्च माह में 22 दिन का वेतन ही दिया जायेगा। 5 अप्रैल को यह लेख प्रेस में देने के समय तक एस्कोर्ट्स के फरीदाबाद प्लान्टों में प्रोडक्शन बन्द हैं और मजदूर हक्के-बक्के हैं। मैनेजमेंट के लिए पत्रे के हिसाब से इस समय आम हालात अच्छे होने के बावजूद 14 दिन से ढाई करोड़ रुपये रोजाना से अधिक का प्रोडक्शन बन्द करवाने के पीछे छिपी मैनेजमेन्ट की साजिश को समझने के लिये कुछ तथ्यों पर थोड़ा विस्तार से गौर करना जरूरी है। आंकड़े हमने मैनेजमेन्ट के प्रकाशन "एस्कोर्ट्स न्यूज" से लिये हैं।

1986 में एस्कोर्ट्स में 382 करोड़ रुपये का प्रोडकशन हुआ। 1987 में 482 करोड़ का और 1988 में 600 करोड़े का। जनवरी-दिसम्बर की जगह बही खातों में हिसाब के लिये 1 अप्रैल से 31 मार्च तय करके मैनेजमेंट ने पिछला साल 15 महीने का बनाया—जनवरी 88 से मार्च 89 तक 783 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ। मैनेजमेन्ट के चेयरमैन ने शेयरहोल्डरों को 20 सितम्बर 89 की मीटिंग में बताया कि अप्रैल से अगस्त 89 के पाँच माह में 308 करोड़ रुपये का प्रोडक्शन हुआ जो कि अप्रैल-अगस्त 88 के 248 करोड़ के उत्पादन के मुकाबले चौंकाने वाली छलांग है। अप्रैल अगस्त 89 में मुनाफा 88 के इसी दौर के मुनाफे से अस्सी प्रतिशत अधिक हुआ। और मैनेजमेंट तथा बिचौलिये प्रचार करते हैं कि मजदूर एक दिन में चार घन्टे ही काम करते है! चूंकि कई मजदूर भी इस प्रचार से प्रभावित हैं। इसलिये ऊपर पूंजीवादी स्त्रोतों से ही आंकड़े दिये हैं ता कि हकीकत की एक झलक दिख सके। दरअसल तोड़-फोड़ प्रोडकशन करके कुछ सुस्ताते मजदूरों को ऊपरी तौर पर देखने से ही ऐसे लगता है कि वर्कर मौज करते हैं। वास्तव में बहुत तेज रफ्तार से काम करके मजदूर अपने मानसिक और शारिरिक स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क करते है शराब और ताश तो बीमारी के लक्षण हैं।

खैर! 3 अप्रेल के टाइम्स आफ इन्डिया में बिचौलियों के चेयरमैन के अनुसार मैनेजमेन्ट ने 50 परसेंट प्रोडक्सन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है—एक साल में 775 करोड़ रुपये की प्रोडक्सन की जगह 1200 करोड़ रुपये का उत्पादन। मैनेजमेन्ट के सरगने की ही तरह चेयरमैन टाइटलधारी बिचौलियों का प्रमुख यह भी कहता है कि 1200 करोड़ रुपये के सालाना प्रोडक्सन के लिये आवश्यक वर्क लोड बढ़ाने के लिये वह और उसके संगी-साथी तैयार हैं पर ...पर मैनेजमेन्ट इस जहर पर चीनी कुछ ढ़ग से लगाये ताकि 1200 करोड़ वार्षिक उत्पादन की स्कीम मजदूरों के मुंह में बिचौलिये ठूंस सकें। यह है 3 अप्रेल के अखबार में बिचौलिया प्रमुख के सार्वजनिक बयान का मतलब।

लेकिन 18 साल से लगातार वर्क लोड बढ़ाने में सहभागी बिचौलिये और उनकी आका मैनेजमेन्ट यह अच्छी तरह जान गये हैं कि अब मजदूरों पर वर्क लोड बढ़ाने के लिये उन्हें कुछ ज्यादा ही पापड़ बेलने पड़ेंगे। हाल ही में मिनी एग्रीमेन्ट के नाम पर 15 परसेंट वर्क लोड बढ़ाने के समय आई दिक्कतें और बिचौलियों द्वारा बार-बार यह घोषणा कि आगे से वर्क लोड नहीं बढ़ाया जायेगा, अभी ताजा घटनायें हैं। **इसलिये मजदूरों को नरम करने के लिये, अपने कन्धों पर बोझा बढ़वाने के लिये मजदूरों को "तैयार करने" के वास्ते 23 मार्च से मैनेजमेन्ट और बिचौलिये प्रोडक्सन बन्द वाला नाटक कर रहे हैं।**

भारत में 20 परसेंट ट्रैक्टर और 40 परसेंट मोटरसाइकिल बनाने वाली एस्कोर्ट्स के 12000 मजदूरों के सामने मामला गम्भीर है। पर मजदूरों का हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहना तो निश्चित तौर पर मैनेजमेन्ट और बिचौलियों की साजिस का शिकार होने की राह है। एस्कोर्ट्स के प्लांटों की 100 करोड़ रुपये की मौडरनाइजेशन स्कीम भी इधर जोर-शोर से जारी है — पता है न कि आयशर ट्रैक्टर में किये गये मौडरनाइजेशन के बाद अब वहां 1100 मजदूरों की जगह मात्र 450 मजदूर ही महीने में 1500 ट्रैक्टर बनायेंगे। एस्कोर्ट्स के प्लांटों में आ रही कम्प्यूटर संचालित मशीनों और नई नई मशीनें खरीदने के लिये मैनेजमेन्ट अधिकारियों के यूरोप-अमरीका दौरों का मजदूरों के लिये मतलब छटनी ही निकलेगा। इन्सैंटिव स्कीम के चक्कर में आने को तेजी से घिसाते एस्कोर्ट्स मजदूरों को समझ लेना चाहिए कि गेंदोर वाले झटके कोई अजूबा चीज नहीं हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का संकट गहरा रहा है और ट्रैक्टर मोटर-साइकिल आदि क्षेत्र में इसकी वजह से लगने वाले पहले झटके में ही इंसैंटिव का पैसा गायब हो जायेगा तथा अभी तक एस्कोर्ट्स में जो नहीं चली है, वह छटनी की तलवार भी मजदूरों के भूंड काटेगी।

एस्कोर्ट्स मजदूरों के हित भी अन्य मजदूरों के हितों की ही तरह पूंजीवादी व्यवस्था को दफना कर उसकी जगह हर्षी-खुशी भरे खुशहाल समाज के निर्माण में है। इसके लिये जरूरी है कि एस्कोर्ट्स मजदूर हर कदम पर मैनेजमेंट, बिचौलियों और इनके राज्य तन्त्र के खिलाफ लड़ें—तभी हकीकत उनके सामने आयेगी और दमन-शोषण वाली इस व्यवस्था को पलटने के लिए वे अन्य मजदूरों के कदमों से कदम मिला कर चल सकेंगे। इस राह पर आगे बढ़ने की पहली शर्त यह है कि एस्कोर्ट्स मजदूर पिछले 18-20 साल से उनकी चमड़ी उतारने में मैनेजमेन्ट की मदद कर रहे बिचौलियों से हिसाब साफ करें। ऐसा करने के लिए साइड मीटिंगों और जनरल बौडी मीटिंगों के जरिए मामलों को बिचौलियों के हाथों से छीनकर अपने हाथों में लेने की कोशिश करना एस्कोर्ट्स मजदूरों का शुरु-आती कदम होगा। हर रोज जलूस निकालना और वर्क लोड बढ़ाने के खिलाफ अड़ना मजदूरों की ताकत बढ़ाने वाले कदम हैं।

एस्कोर्ट्स को पार्टस सप्लाई करने वाली दो हजार से ज्यादा फैक्ट्रियाँ तो फरीदाबाद में ही हैं इन एनसीलरियों में 400-500-600 रुपए महीने में काम करते दसियों हजार मजदूरों की डिमांडों को सक्रिय तौर पर उभार कर एस्कोर्ट्स मजदूर एक शक्तिशाली मजदूर आन्दोलन के लिए हालात बना सकते हैं। आज की हालात में एक फैक्ट्री, एक कम्पनी के मजदूर अकेले दम पर अपने रोजमर्रा के हितों की देखभाल भी नहीं कर सकते तीखा होना और फैलता संघर्ष ही अब मजदूरों की सफलता की राह है। और जैसे कि कानपुर के कपड़ा मजदूरों ने फरवरी 89 में पांच दिन रेलवे लाइन जाम करके सफलता हासिल करके दिखाया है, गेट पर ताश खेलने या फैक्ट्री में गप्प मारने की बजाय पूंजीवादी तन्त्र के नाजुक अंगों पर चोट मारना मजदूरों की ताकत बढ़ाता है इस सब के लिए जरूरी है कि बिचौलियो को मजदूर ठोकर मारें तथा पहल कदमी अपने हाथों में लें। मैनेजमेंट और बिचौलियों पर आस लगाना मजदूरों की बरबादी की राह है।

(प्रथम पेज का शेष)

मैनेजमेंट के दमन-शोषण को झेलते और कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाते, जुलाई 1987 में चुने लोगों की अपील पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने आखिर कर फैसला दिया कि कांग्रेस-सी पी एम सयुक्त कमेटी को प्रतिनिधि यूनियन के तौर पर हिन्दुस्तान लीवर मैनेजमेंट द्वारा दी गई मान्यता गैर-कानूनी है। हाई कोर्ट ने 20 अक्तूबर 1989 को यूनियन के चुनाव कर वाने की घोषणा की और इस काम के लिये दो स्पेशल अधिकारी नियुक्त किये। मैनेजमेंट ने उस दिन फैक्ट्री में चुनाव करवाने का हाई-कोर्ट को आश्वासन दिया।

20 अक्तूबर 1989 को नाटक हुआ। फैक्ट्री में मजदूर वोट डालने के लिये लाइन लगाये खड़े रहे पर कोई वोट नहीं पड़े। हिन्दुस्तान लीवर मैनेजमेन्ट, पुलिस और कांग्रेस - सी पी एम सयुक्त कमेटी ने हाई कोर्ट के स्पेशल अधिकारियों को डरा धमका कर चुनाव नहीं होने दिया। इस पर हाई कोर्ट के स्पेशल अधिकारियों ने मैनेजमेंट के दो लोगों के खिलाफ तो केस भी कर दिया है और केस चल रहा है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिन्दुस्तान लीवर में यूनियन चुनाव की नई तारीख और नये स्थान का आदेश दिया तथा इस काम के लिये दो नये वकील स्पेशल अधिकारी नियुक्त किये। हाई कोर्ट ने यूनियन चुनाव 28 जनवरी 90 वाले इतवार को गार्डन रीच थाने में अथवा म्युनिसिपल कारपोरेसन के दफ्तर में करवाने का हुक्म दिया हाई कोर्ट के स्पेशल अधिकारियों को 26 जनवरी को पुलिस ने कहा कि थाने में वोट नहीं डलवाये जा सकते। और कारपोरेशन पर काबिज सी पी एम-कांग्रेस मेम्बरों ने कलकत्ता की 300 वीं सालगिरह का कार्यक्रम बता कर जगह देने से इन्कार कर दिया—वैसे 28 जनवरी को वहां कोई कार्यक्रम नहीं हुआ और इतवार होने के नाते दिनभर दफ्तर के ताले लगे रहे। खैर हिन्दुस्तान लीवर की यूनियन के चुनाव फिर भी नहीं हुये। राम नाम सत्त है यह पूंजीवादी नृत्य है।

लगता है कि हाई कोर्ट का नाटक अभी जारी रहेगा। इधर मैनेजमेन्ट, पुलिस व दल्लों ने मजदूरों पर हमले तेज कर दिए है। 300 ठेका और 27 परमानेंट मजदूर गेट के बाहर हैं, 21 मजदूरों पर पुलिस ने केस बना दिए हैं।

हिन्दुस्तान लीवर के मजदूरों के खिलाफ कांग्रेस-सी पी एम संयुक्त कमेटी लाल और तिरंगे झन्डों के साथ कलकत्ता की सड़कों पर जलूस निकाल रही है। प्रगतिशील और वाम शक्तियों के मन्त्र जपने वाले तो खैर आँख मूंदे अपना जप जारी रखेंगे और कुछ लोगों का इन जलूसों से मनोरजन हो रहा है, लेकिन मजदूरों को नतीजे निकालने चाहियें। **नकली कम्युनिस्टों और उनके फर्जी लाल झन्डों को ठोकर मारना जरूरी है पर पूर्वी यूरोप के मजदूरों की तरह ऐसा करके भगवा झन्डा थाम लेना तवे से चूल्हे में कूदना होगा। मजदूर वर्ग के क्रान्तिकारी सिद्धान्त, मार्क्सवाद को अपनाना और वर्तमान से निपटने के लिए उसका विकाश करना कठिन काम है—पर दूसरी कोई राह मजदूरों के लिये नहीं है।**

अन्य स्थानों के मजदूरों के अनुभवों की तरह कलकत्ता में हिन्दुस्तान लीवर के मजदूरों के अनुभवों की भी यही सीख है कि पूंजीवादी कायदे-कानून के भ्रमजाल से मजदूर अपने को निकालें। हिन्दुस्तान लीवर के मजदूरों का दुख-दर्द इस हकीकत को भी साफ तौर पर सामने लाया है कि संघर्ष को फैलाना और तीखा करना ही आज की हालात में मजदूरों की सफलता की राह है। इसके लिए जरूरी है कि अलग-अलग फैक्ट्रियों के मजदूर एक-दूसरे की मदद करें।

स्वत्वाधिकारी व सम्पादक शेर सिंह द्वारा आटोपिन झुग्गी, फरीदाबाद से प्रकाशित व अलकनन्दा प्रिंटिंग प्रेस C-III/206, सं. गाँ. मेमो. न. से मुद्रित